

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2008
को उत्तर के लिए नियत 11.03.2025
ईवी चार्जिंग सुविधाओं के बारे में नीतियां

.2008श्री सुधीर गुप्ता :

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कितनी है और उक्तके दौरान विक्रय किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 2024 देश में (क)
; हैअवधि के दौरान वाहनों की कुल बिक्री का प्रतिशत क्या

तक इलेक्ट्रिक 2030 की एक रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई कैप्सक्या (ख)वाहन की बिक्री 27
प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शनों पर खराब पित चार्जिंग स्टेशनों की कमी और स्था भागों में चार्जिंग स्टे देश के विभिन्नक्या (ग)

;ह कम हो रहा हैउत्साओं का इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिसेवा सुविधाओं के कारण उपभोक्ता

यदि हां (घ), तो सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

और चार्जिंग सुविधाओं शनों की कम संख्या नीतियों के कारण चार्जिंग स्टेष्ट सरकार की अस्पक्या (ड)

और ;की दयनीय स्थिति है

यदि हां (च), तो सरकार द्वारा संपूर्ण देश में ईवी चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण के
संबंध में क्या ठोस नीतियां बनाई गई हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

)श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा(

(क) : कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान देश में कुल 19.50 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। ये
इलेक्ट्रिक वाहन कैलेंडर वर्ष 2024 में बिके कुल वाहनों का 7.44 प्रतिशत थे।

कैलेंडर वर्ष	वाहन पर कुल पंजीकृत ईवी	वाहन पोर्टल पर पंजीकृत कुल वाहन	ईवी की हिस्सेदारी का %
	(क)	(ख)	(ग)=(क)/(ख)
2024	19,50,490	2,62,07,453	7.44%

स्रोत: वाहन

(ख) :सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 से ईवी पंजीकरण कई गुना बढ़ा है:

तालिका: 2014-15 से ईवी की पैठ

लाख में

वित्त वर्ष	पंजीकृत आईसीई वाहनों की संख्या	पंजीकृत ईवी वाहनों की संख्या	कुल पंजीकृत वाहनों में ईवी का %
2014-15	193.98	0.02	0.01%
2015-16	201.06	0.16	0.08%
2016-17	215.96	0.56	0.26%
2017-18	238.63	0.96	0.40%
2018-19	251.7	1.47	0.58%
2019-20	244.2	1.74	0.71%
2020-21	173.79	1.43	0.82%
2021-22	179.86	4.59	2.49%
2022-23	211.49	11.83	5.30%
2023-24	229.6	16.81	6.82%
2024-25	225.87	17.84	7.31%

ईवी की पैठ में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है।

(ग) से (ड) : भारत सरकार देश में चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए निरंतर सहायता दे रही है। फेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 839 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(च) : विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना संस्थापन और प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश-2024" को 17.09.2024 को जारी किया है जिसमें देश में ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना संबंधी मानकों और प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने "बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन संस्थापन तथा प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश" 10.01.2025 को जारी किए हैं। ये दिशानिर्देशों का लक्ष्य देश में सशक्त ईवी चार्जिंग अवसंरचना को आसान बनाना है।
